त्वरित आर्थिक विकास को 2500 करोड़

त्वरित आर्थिक विकास योजनाओं के लिए बजट में 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए एक हजार करोड़ का प्रावधान है। जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष परियोजनाओं के लिए 10 करोड़ दिए जाएंगे।

10
करोड़ रुपये बुंदेलखंड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए

त्वरित आर्थिक विकास योजना के जरिये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालयों के भवन निर्माण, स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित भवन निर्माण, जलापूर्ति, जल की निकासी, लघु सिंचाई, वनीकरण, विद्युतीकरण, शहरी क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण, सेतु निर्माण, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क का निर्माण और न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के चैंबर का निर्माण कराया जाता है। प्रदेश सरकार ने 2018 में इसके मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन करते हुए योजना में राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज और राजकीय आईटीआई संस्थानों के भवन निर्माण को भी शामिल किया है। सरकार सरकारी संपत्तियों की जियो टैगिंग, गूगल मैपिंग और उनके संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना लागू कर रही है।

5 साल में 1.66 लाख करोड़ बढ़ा बजट

यूपी सरकार का बजट साल दर साल बढ़ता जा रहा है। विकास के रथ पर सवार प्रदेश का बजट पांच साल में 1.66 लाख करोड़ बढ़ चुका है।